

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2021—आश्विन 9, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अगस्त 2021

क्रमांक ई 1-23/2016/एक-2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 6/12/2016-EO(MM-I), दिनांक 06-08-2021 तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 154/CGH/2021-P.Admn, दिनांक 17-08-2021 द्वारा प्राप्त सहमति उपरान्त राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. देवासेनापति, भा.प्र.से. (2007), अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को निदेशक, जनगणना/निदेशक, नागरिक पंजीकरण, छत्तीसगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 4-06/30/सं./2021.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य के होनहार किन्तु अर्थाभावग्रस्त युवा कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण/शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**— यह नियम “अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, 2021” कहलाएगा.
2. **परिभाषाएं.**—
 - (1) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
 - (2) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (3) “विभाग” से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
 - (4) “संचालनालय” से अभिप्रेत है; संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़;
 - (5) “संचालक/आयुक्त” से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़;
 - (6) “वर्ष” से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समयावधि;
 - (7) “अर्थाभावग्रस्त कलाकार” से अभिप्रेत है ऐसे कलाकार/छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय रुपये 72000/- से अधिक न हो;
3. **प्रदर्शनकारी कला/विधाएं जिनके लिए छात्रवृत्ति दी जा सकेगी.**—

क्र.	विधाएं	उप विधाएं
01.	लोक/पारंपरिक जनजातीय कलाएं	— छत्तीसगढ़ की समस्त पारंपरिक जनजातीय और लोक नाट्य, नृत्य, गीत/संगीत, खेल, चंदैनी, भरथरी, गोपी-चंदा, पंडवानी, घोटुल पाटा, धनकुल जगार तथा छत्तीसगढ़ की अन्य पारंपरिक लोक जनजातीय गाथाएं, वाद्य, पाक कला, सौंदर्यकला, गायन, वादन आदि.
02.	शास्त्रीय संगीत	— हिन्दुस्तानी (गायन/वादन) एवं कर्नाटिक (गायन/वादन) आदि.
03.	शास्त्रीय नृत्य तथा नृत्य संगीत	— भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहनीअट्टम, ओडिसी, मणीपुरी, कथकली, ओडिसी नृत्य एवं संगीत आदि.
04.	रंगमंच	— हिन्दी और छत्तीसगढ़ी नाट्य मंचन, नाचा, भतरा, नाट तथा अन्य लोक जनजातीय नाट्य विधा सहित.
05.	दृश्य कला	— ग्राफिक्स, मूर्तिकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मृद्भाण्ड तथा मृणकला (Ceramics) छत्तीसगढ़ के विविध लोक जनजातीय परंपराओं के चित्रांकन की विधा आदि.
06.	सुगम शास्त्रीय संगीत	— ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि कव्वाली, गज़ल आदि.

4. **उद्देश्य.—**

- (1) राज्य के ऐसे छात्र/छात्राएं जो संगीत, नृत्य, प्रदर्शनकारी कला विधा में शिक्षा/उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत को छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- (2) गुरुशिष्य परंपरा के तहत पारंपरिक लोक कलाएं सीखने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- (3) संस्कृति संचालनालय द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित कलाकारों/छात्रों को महत्वपूर्ण विधा जो क्रमांक 03 में वर्णित है, के लिए

5. **पात्रता.—** छात्रवृत्ति के लिए आवेदक की पात्रता की सामान्य शर्तें/निबंधन निम्नानुसार होंगी :—

यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी ऐसे कलाकारों/छात्रों के लिए खुली रहेगी, जो नीचे रखी अर्हता रखते हों—

- (1) छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हो;
- (2) आवेदक अथवा उनके परिवार की वार्षिक आय रुपये 72,000/- से अधिक न हो;
- (3) आवेदक की आयु 15 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो;
- (4) ऐसे आवेदक जिन्हें भारत सरकार/छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की किसी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति दी जा रही है, इसके लिए पात्र नहीं होंगे;
- (5) लोक विधा में इस योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा;
- (6) गुरुशिष्य परंपरा के अंतर्गत विगत 6 माह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. प्रत्येक जिले से ऐसे 2 प्रशिक्षार्थी को जिलाध्यक्ष की अनुशंसा से;
- (7) स्कूल शिक्षा-मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में अध्ययनरत मैट्रिक (10+2)/समकक्ष में अध्ययन के लिए संस्था प्रमुख की अनुशंसा से,
- (8) उच्च शिक्षा-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर/समकक्ष, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पूणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए संस्था प्रमुख की अनुशंसा से,

6. आय के सत्यापन के संबंध में विधिवत् शपथ-पत्र (Affidavit) निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-दो) में अथवा अपने जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र-परिशिष्ट-तीन के अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है.

7. **छात्रवृत्ति की अवधि.—**

- (1) चयनित छात्र/छात्राओं/प्रशिक्षार्थी को 01 वर्ष के लिए देय होगी.
- (2) सामान्यतया उच्च प्रशिक्षण/आगामी प्रशिक्षण गुरुशिष्य परम्परा के अन्तर्गत अथवा देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्था/अपने गुरु से प्राप्त किया जा सकेगा.
- (3) प्रशिक्षणार्थी द्वारा पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है तथा प्रशिक्षणान्तर्गत संबंधित विधा में सैद्धांतिक विषय (यदि हो तो), के अध्ययन के अतिरिक्त नियमित रियाज़/अभ्यास अपेक्षित होंगे.

8. छात्रवृत्ति की राशि.—

- (1) छात्रवृत्ति मासिक होगी जिसमें यात्रा, पाठ्यपुस्तकों, कला सामाग्रियों अथवा अन्य उपकरणों तथा प्रशिक्षण प्रभार पर व्यय आदि, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।

क्र.	स्तर का विवरण	मासिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि	प्रतिवर्ष चयनित छात्र/छात्रा/ प्रशिक्षार्थी की संख्या	कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रशिक्षण संस्था/गुरुशिष्य परंपरा	5000/-	56	2.80 लाख
2.	स्कूल शिक्षा	8000/-	30	2.40 लाख
3.	उच्च शिक्षा	10000/-	15	1.50 लाख
कुल राशि				6.70 लाख
शब्दों में कुल राशि रु. छै लाख सत्तर हजार मात्र				

- (2) चयनित आवेदकों द्वारा संबंधित संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें देय छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रतिवर्ष डिमांड ड्राफ्ट/ऑन लाइन किया जाएगा।
- (3) प्रशिक्षणावधि में प्रशिक्षार्थी का शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक छः महिने के अंतराल में किया जावेगा एवं प्रगति संतोषप्रद न पाये जाने पर देय राशि की अगली किस्त रोकी जा सकेगी।

9. आवेदन प्रक्रिया.—

- (1) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन/प्रविष्टियां आमंत्रण हेतु प्रतिवर्ष राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जनसम्पर्क संचालनालय/संस्कृति विभाग के वेबसाईड के माध्यम से प्रकाशित/प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।
- (2) आवेदन-पत्र संबंधित संस्था प्रमुख के नाम से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-एक) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) किसी भी आवेदक द्वारा चयन न होने की स्थिति में योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता का दावा नहीं किया जा सकेगा और न ही उक्त संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा।

10. आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न.—

- (1) शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि की पुष्टि हेतु प्राप्त उपाधी, पत्रोपाधि (डिप्लोमा) तथा प्रमाण-पत्रों, प्रशस्ती पत्रों आदि की सत्यापित छाया प्रतिलिपि;
- (2) आयु प्रमाण-पत्र अथवा मैट्रिक/10+2 अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतिलिपि (जन्मपत्री को छोड़कर);
- (3) हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साईज की एक फोटो, शास्त्रीय नृत्य के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए वेशभूषा एवं विभिन्न नृत्य मुद्राओं के साथ लिए गए फुल साईज के तीन अतिरिक्त फोटोग्राफ;
- (4) पेंटिंग, मूर्तिकला तथा व्यावहारिक कलाओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के साथ उत्कृष्ट स्तर के मूल कला कृतियों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रतिलिपि संलग्न होना चाहिए तथा संगीत के लिए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उत्कृष्ट प्रस्तुति की एक ऑडियो रिकार्डिंग भेजा जाना चाहिये।

ललित कला जैसे दृश्य कला के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि आवश्यक है;

- (5) पूर्णरूप से भरे गये आवेदन पत्र संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाना चाहिए. अपूर्ण आवेदन पत्रों अथवा निर्धारित प्रपत्र से भिन्न आवेदन प्रपत्र अथवा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा;

- (6) लोक एवं जनजातीय आवेदनकर्ताओं को निर्दिष्ट आवेदन पत्र में वांछित जानकारी के साथ अपने गुरु, जिनके माध्यम से वे संबंधित सृजनात्मक अथवा प्रदर्शनकारी कला को सीख रहे हैं से अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदनकर्ता अपने गुरु से कितने वर्षों से यह प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा उन्होंने कितनी अवधि से संदर्भित विधा का प्रदर्शन किया है। इन आवेदनकर्ताओं के संबंध में किसी और उपाधि/पत्रापाधि संबंधित अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- (7) अंतिम चयन उपरान्त चयन परिणाम की जानकारी केवल चयनित उम्मीदवारों को डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी;
- (8) पते में परिवर्तन होने पर जानकारी तत्काल विभाग को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए उस विषय का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए जिसके लिए आवेदन भेजा गया है;
- (9) उक्त नियमों में यथोचित संशोधन/परिवर्तन का अधिकार शासन को होगा;

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 4-07/सं./30/2021.—राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के रामायण मंडलियों के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु “रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2021” के अंतर्गत कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/पुरस्कार हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.—

- (1) ये नियम “रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2021” कहलायेंगे।
- (2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
- (2) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।
- (3) “विभाग” से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग।
- (4) “संचालनालय” से अभिप्रेत है संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व।
- (5) “संचालक/आयुक्त” से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व।
- (6) “समिति” से अभिप्रेत है इस नियम के कंडिका 7 के अंतर्गत गठित समिति।
- (7) “रामायण मंडली” से अभिप्रेत है विविध लोक कलाओं, नृत्य-संगीत, टीकाकार, छत्तीसगढ़ी, गीतकार, वाद्ययंत्र वादक।

3. उद्देश्य.—

- (1) राज्य के रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करना।
- (2) प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाने में अपना सतत् योगदान देने वाले रामायण मंडलियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- (3) लोक कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/पुरस्कार की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाना।

4. चयन प्रक्रिया.—

- (1) दैनिक समाचार पत्रों तथा संचालनालय के सूचना पटल, सोशल मीडिया एवं वेबसाईट के माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाएगी।
- (2) ग्राम पंचायत स्तर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त चयनित मंडली का नाम ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।

- (3) ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त चयनित मंडली का नाम एस.डी.एम./सीईओ द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रेषित करना.
- (4) जिला स्तर पर चयनित प्रथम स्थान प्राप्त मंडली का नाम जिला कलेक्टर द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिये संस्कृति विभाग को प्रेषित करना.

5. **पात्रता.—**

- (1) छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हो.
- (2) छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा पर आधारित विधा में सक्रिय हो.
- (3) संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत हो.
- (4) पंजीकृत रामायण मंडलियों को वाद्ययंत्र क्रय के लिए वित्तीय वर्ष में 1 बार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा आगामी 2 वर्षों के लिए अपात्र होंगे.
- (5) तीन वर्षों से कम कला दल/कलाकार जो गांवों/कस्बों/ग्रामीण इलाकों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से लोकप्रियता हासित कर चुके हैं एवं नवोदित कलाकार जो लोक कला के संरक्षण, संवर्धन में योगदान दे रहे हैं.

6. **प्रोत्साहन राशि.—** प्रोत्साहन/पुरस्कार राशि ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा.—

क्र.	स्तर का नाम	विवरण	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ग्राम पंचायत स्तर (लगभग 12000)	प्रतियोगिता के प्रथम स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडली को प्रोत्साहन राशि.	5000/-	600.00
2.	ब्लॉक स्तर (146)	प्रतियोगिता के प्रथम स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडली को प्रोत्साहन राशि.	10,000/-	14.60
3.	जिला स्तर (28)	प्रतियोगिता के प्रथम स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडल को प्रोत्साहन राशि.	50,000/-	14.00
4.	राज्य स्तर	प्रतियोगिता के प्रथम स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडली को प्रोत्साहन राशि.	5.00 लाख	10.00
		प्रतियोगिता के द्वितीय स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडली को प्रोत्साहन राशि.	3.00 लाख	
		प्रतियोगिता के तृतीय स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडली को प्रोत्साहन राशि.	2.00 लाख	
5.	चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मंडलियों को विशेष प्रोत्साहन.	विभागीय समिति द्वारा अवलोकन/परीक्षण उपरांत प्रत्येक रामायण मंडली को वाद्य यंत्र क्रय के लिए प्रोत्साहन. (लगभग 7000 मंडलियाँ ग 5000/-)	5,000/-	350.00
			कुल राशि	988.60

शब्दों में कुल राशि रु. नौ करोड़ अठ्यासी लाख साठ हजार मात्र

7. निर्णायक मंडल का गठन.—

- (1) ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच/सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें 1 सदस्य लोक कला से संबंधित हो।
- (2) ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन हेतु एस.डी.एम. की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें 1 सदस्य लोक कला से संबंधित हो।
- (3) जिला स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 1 सदस्य लोक कला से संबंधित हो।
- (4) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु संस्कृति विभाग द्वारा 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे.—

क्र. (1)	विभागीय चयन समिति के गठित सदस्य (2)	संख्या (3)
1.	संचालनालय के आयुक्त/संचालक (अध्यक्ष)	01 – शासकीय अध्यक्ष
2.	संचालनालय स्तर पर (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)	02 – शासकीय सदस्य
3.	खैरागढ़ के कुलपति/नामांकित	01 – अशासकीय सदस्य
	दूरदर्शन या आकाशवाणी के J ग्रेड के सदस्य/कलाकार	01 – अशासकीय सदस्य

- (5) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी निर्णायक मंडल का सदस्य नहीं होगा जो प्रतियोगिता से संबंधित हो/भाग लिया है।
- (6) निर्णायक मंडल के सदस्यों को नियमानुसार मानदेय/यात्रा भत्ता देय होगा।

8. प्रशासनिक विभाग/नोडल एजेंसी.—

- (1) इस योजना का प्रशासनिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन का संस्कृति विभाग होगा तथा इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर होंगी।
- (2) किसी भी व्याख्या संबंधी विवाद अथवा अन्य विवाद पर संचालक, संस्कृति का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) यह योजना एक प्रोत्साहन के रूप में है, इसके संबंध में कोई अपील अथवा न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

9. नियमों में संशोधन.— यदि इन नियमों के किसी उपबंधों में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त संबंध में यथोचित कारण दर्शाते हुए नियमों में संशोधन किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अगस्त 2021

क्रमांक 1829/आर-489/2011/ऊ.वि./13/1.—विभाग के आदेश क्रमांक 1128/आर-489/2011/ऊ.वि./13/2 दिनांक 25-05-2011 द्वारा राज्य में स्थापित बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों में बायोमास एवं कोयले के मिश्रण हेतु निर्धारित अनुपात निरीक्षण हेतु राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन किया गया है।

2. राज्य शासन एतद्वारा उक्त राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का पुनर्गठन करते हुए निम्नानुसार समिति का गठन करती है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	समिति में पद (3)
1.	मुख्य अभियंता, (संचा./संधा.), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर.	अध्यक्ष
2.	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा नामित मुख्य अभियंता से अनिम्न स्तर के अधिकारी.	सदस्य
3.	खाद्य विभाग द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4.	क्रेडा मुख्यालय के बायोमास कार्यक्रम प्रभारी अधीक्षण अभियंता	संयोजक सदस्य
5.	क्रेडा द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	सदस्य

3. समिति के कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व में जारी आदेश दिनांक 25-05-2011 अनुसार रहेगी.

4. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्रमांक 1958/एफ 12/03/2017/13/2/ऊ.वि.—चूंकि, राज्य शासन की यह राय है कि राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 के अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना जनहित में आवश्यक हो गया है कि उक्त नीति के तहत 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2027 की अवधि में प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा स्वयं के लिए की गई विद्युत की खपत (आक्जलरी खपत) एवं राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा-3 (ब) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 की कंडिका-8 (ब) के अनुपालन में, सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा, सौर ऊर्जा नीति 2017-27 की प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले पात्रता धारित नवीन सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों को विद्युत शुल्क के भुगतान से विहित शर्तों एवं प्रक्रिया/प्रावधानों के तहत शत प्रतिशत छूट प्रदान करती है :—

1. सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 के तहत, केवल 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 की अवधि में प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा स्वयं के लिए की गई विद्युत की खपत (आक्जलरी खपत) एवं राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी.
2. राज्य की औद्योगिक नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन/रियायतें, सौर ऊर्जा नीति की तुलना में निम्नतर होने पर, सौर ऊर्जा नीति के प्रावधान लागू रहेंगे.

3. विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी किये गये स्थाई विद्युत कनेक्शन की तारीख से संयंत्र के संचालन की अवधि के लिए लागू रहेगी.
4. चूंकि यह अधिसूचना भूतलक्षीय तारीख 01 अप्रैल 2017 से लागू की जा रही है, अतः अपवाद स्वरूप अधिसूचना जारी होने की तारीख पर राज्य की सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थापित ऐसे विद्यमान इकाईयों, को जो 01 अप्रैल 2017 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुके हैं, को विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख से 90 दिवस की समय-सीमा में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) से अनुशंसित आवेदन, मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा.
5. अधिसूचना जारी होने के पश्चात् स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 में अनुबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से निर्धारित अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन 90 दिवस की समय-सीमा में क्रेडा को प्रेषित करेगा.
6. उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन का मुख्य विद्युत निरीक्षक नियमानुसार परीक्षण एवं संयंत्र का निरीक्षण कर, विद्युत शुल्क से भुगतान से छूट हेतु पात्र पाये गये आवेदकों को, 30 दिवस के भीतर सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 में यथा उल्लेखित कालावधि के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा.
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त अथवा सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 में अनुबद्ध प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता स्वमेव निरस्त मानी जायेगी.
8. उपयुक्त पैरा-(7) में यथा विहित पात्रता के रद्द माने जाने की दशा में, ऐसे इकाई को ब्याज सहित विद्युत शुल्क की राशि राज्य के राजकोष में वापस जमा करनी होगी, यदि ऐसी राशि राजकोष में जमा नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जायेगा.
9. विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता के संबंध में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर, विवाद का निराकरण छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम-13 के प्रावधानों के अंतर्गत ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस हेतु अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा और अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा.

यह अधिसूचना “सौर ऊर्जा नीति, 2017-27” के प्रभावी होने की तारीख अर्थात् भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 अप्रैल 2017 से प्रभावशील होगी तथा 31 मार्च 2027 तक प्रभावशील रहेगी.

S. No. 1958/F 12/03/2017/13/2/E.D.—Whereas, it is the opinion of the State Government that according to the State's Solar Energy Policy 2017-27, it has become necessary in public interest to do so, to encourage Solar Power Generation in the State that comes under the said policy from 01 April, 2017 to 31 March, 2027 during the period, payment of electricity duty should be exempted on the consumption (auxiliary consumption) of electricity for self by the Solar Power Plants installed in the State and on captive consumption within the State;

Now therefore, powers conferred by Section 3-b of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949), in compliance with Clause-8 (B) of the State's Solar Energy Policy 2017-27, the State Government, hereby, gives 100% exemption from the payment of electricity duty to the new solar power generation plants which have attained eligibility, to be set up in the effective period of the Solar Energy Policy, 2017-27 under the terms and procedures / provisions, for the promotion of the investment in the field of solar power generation :-

1. Under the Solar Energy Policy, 2017-27, only during the period April 01, 2017 to March 31, 2027, solar plants installed in the State will be exempted from the payment of electricity duty on the consumption (auxiliary consumption) of electricity for self and on captive consumption within the State.
2. In case of the incentives / concessions provided in the industrial policy of the state are lower than the solar energy policy, the provisions of solar energy policy will remain in force.

3. The exemption from payment of electricity duties will be applicable for the period of operation of the plant from the date of permanent power connection issued by Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited.
4. Since this notification is being implemented with retrospective effect from 01 April 2017, the existing units installed under the solar energy policy of the State on the date of issue of notification as an exception, have started commercial production after 01 April 2017, in order to get the facility of duty exemption, the recommended application from Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency(CREDA) will have to be submitted in the Chief Electrical Inspectorate Office within a time limit of 90 days from the date of issue of notification.
5. Solar Power Plant installed after issuing notification shall apply to the CREDA within the period of 90 days for the exemption of payment of the electricity duty for prescribed period from the date of commencement of the Commercial Operational as per provision stipulated in the Solar Energy Policy 2017-27.
6. As above, Chief Electrical Inspector shall issue a certificate within 30 days after examining the application and inspecting the plant as per rule to applicants found eligible for exemption from payment of electricity duty for the period as mentioned in the Solar Energy Policy, 2017-27.
7. In case of any violation of the conditions mentioned in the certificate issued by the Chief Electrical Inspector or provisions stipulated in the Solar Energy Policy, 2017-27, the eligibility for exemption from payment of electricity duty shall automatically be deemed revoked.
8. In case of the cancellation of eligibility as prescribed in para-7 above, such unit will have to deposit the sum of electricity duty with interest to State treasury, if such amount is not deposited in the treasury, it shall be recovered as arrears of land revenue.
9. In case of dispute regarding eligibility for exemption of electricity duty, the dispute will be resolved under the provisions of Rule 13 of Chhattisgarh Electricity Duty Rules, 1949, by the authority authorized by the Department of Energy, Government of Chhattisgarh and authorized decision will be binding on both sides.

This notification shall come in to force from the date of effect of "Solar Energy Policy, 2017-27" i.e. with retrospective effect from 01 April 2017 and will remain in effect till 31 March 2027.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 10-6/2021/16.—भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 सहपठित भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 की धारा 2(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा नियुक्त श्रम कल्याण अधिकारियों को “उपकर संग्रहक” नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 669/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	कुंवरा प.ह.नं. 42	0.96	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नवागढ़.	ढाबा व्यपवर्तन के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 670/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	कुंवरा प.ह.नं. 42	1.97	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नवागढ़.	ढाबा व्यपवर्तन के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 11 अगस्त 2021

क्रमांक 811/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	कातलबोड़ प.ह.नं. 42	2.08	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नवागढ़.	ढाबा व्यपवर्तन के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोस्कर विलास संदीपान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोटमार प.ह.नं. 39	3.480	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	सपनई बैराज वितरक व लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जुलाई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202101042900045/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	नहरपाली प.ह.नं. 31	2.132	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, संभाग रायगढ़.	हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग में भूपदेवपुर राबर्ट्सन के मध्य रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 जुलाई 2021

क्रमांक 34/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	गंगापुरखुर्द प.ह.नं. 21	0.365	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.).	औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्रमांक/4530/वा./भू.अ./प्र.क्र./27/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
PRF कक्ष क्रमांक 970 में से	3.78
PRF कक्ष क्रमांक 970 में से	1.70
योग	5.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहकसा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-जोबरो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
332/1	0.028
333/8	0.028
332/4	0.024
333/9	0.036
332/2	0.016
340	0.072
332/3	0.020
333/2	0.036
333/7	0.024

योग 09 0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रायगढ़-हमीरपुर मार्ग सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 सितम्बर 2021		(1)	(2)
<p>क्रमांक 07/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—</p>		357/1	0.121
		103/2	0.101
		96/2	0.008
		184/1	0.053
		221/1	0.120
		307/3	0.027
		225/1	0.072
		222/2	0.032
		238/1	0.053
		209	0.020
		97/1	0.032
		235/1	0.057
		234/2	0.036
		185/1	0.033
(1) भूमि का वर्णन-		22/1	0.072
(क) जिला-रायगढ़		23/1	0.137
(ख) तहसील-रायगढ़		276	0.032
(ग) नगर/ग्राम-बड़माल		356/1	0.020
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.535 हेक्टेयर		104	0.048
खसरा नम्बर		96/1	0.032
रकबा		184/2	0.008
(1)		247/1ख	0.089
(2)		307/4	0.044
221/4	0.040	188/3	0.040
265/1	0.077	309/1	0.153
217/1	0.020	307/1	0.016
233/2	0.037	221/2	0.121
208	0.028	68/2	0.020
376/2	0.008	310/1	0.041
239/2	0.110	235/2	0.032
272/1, 273/1	0.048	196/1	0.121
280/1	0.097	22/2	0.065
343/1	0.101	26/1	0.051
281	0.089	277/1	0.052
11	0.016	409/1	0.020
109, 110	0.081	357/2	0.045
220/1	0.032	106/1	0.016
246	0.060	120/1, 120/2, 120/3	0.040
310/3	0.016	179/3ख	0.012
183/2	0.028	308/3	0.058
221/5	0.085	213/3	0.028
279	0.008	308/1	0.202
251/3	0.036	307/5	0.014
111/2	0.032	250/1	0.028
237/1	0.061	377/2	0.012
180/1	0.069	310/2	0.075
189	0.004	235/3	0.154
274	0.020		

(1)	(2)	(1)	(2)
376/1	0.008	207/1	0.028
239/1	0.114		
266/1	0.101	योग	84
278/1	0.012		4.535
103/1	0.125	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी	
266/2	0.121	तलाईपाली कोल माईस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.	
106/3	0.033	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
113/2/2, 113/3/2, 114/2/2	0.040	(राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
311/2	0.004		
248/2	0.028	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
313/2	0.054	भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 31 अक्टूबर 2020

क्रमांक/4216/वित्त लि. 01/2020.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो अनु क्रमांक 04 के नियम 08 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं शिव अनंत तायल, कलेक्टर, बेमेतरा वर्ष 2021 हेतु बेमेतरा जिला में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं के लिये निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्र.	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	गणेश चतुर्थी	10-09-2021	शुक्रवार
02.	दशहरा (महानवमी)	14-10-2021	गुरुवार
03.	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	05-11-2021	शुक्रवार

शिव अनंत तायल,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/1161.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/3704 रायपुर दिनांक 28-10-2020 द्वारा श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर जिला बस्तर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 01 एक/ज्ये.लि.-दो/2021 दिनांक 17-06-2021 द्वारा श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर जिला बस्तर का राज्य शासन के आदेशानुसार स्थानांतरण दुर्ग होने के फलस्वरूप श्री जी.आर. मरकाम, संयुक्त कलेक्टर, जिला बस्तर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर को मण्डी समिति जगदलपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर जिला बस्तर के स्थान पर श्री जी.आर. मरकाम, संयुक्त कलेक्टर, जिला बस्तर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 26 जून 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/1258.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/4971 रायपुर दिनांक 09-10-2015 द्वारा श्री पी.आर. बघेल, सहायक संचालक (कृषि) दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/2124/कृ.उ.मं./2021 दंतेवाड़ा दिनांक 13-04-2021 द्वारा श्री आनंद सिंह नेताम, उप संचालक (कृषि) दंतेवाड़ा को कृषि उपज मंडी समिति गीदम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री पी.आर. बघेल, सहायक संचालक (कृषि) दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के स्थान पर श्री आनंद सिंह नेताम, उप संचालक (कृषि) दंतेवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/1435.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/3314 रायपुर दिनांक 07-10-2020 द्वारा श्री बी.एल. साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/200/उ.लि./2021 दिनांक 17-06-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति भटगांव में पदस्थ भारसाधक अधिकारी श्री बी.एल. साहू वरिष्ठ विकास अधिकारी बिलाईगढ़ के दिनांक 30-06-2021 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री एल.पी. देवांगन कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री बी.एल. साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ के स्थान पर श्री एल.पी.देवांगन कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/1779.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./10-11/7574 दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री आर.एस. तोमर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल को कृषि उपज मंडी समिति कसडोल का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का ज्ञापन क्रमांक/228/उ.लि./2021 दिनांक 08-07-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कसडोल के भारसाधक अधिकारी श्री आर.एस. तोमर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल का दिनांक 30-06-2021 को सेवानिवृत्त हो जाने कारण उनके स्थान पर श्री बलराम सिंह ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल को कृषि उपज मंडी समिति कसडोल के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री आर.एस. तोमर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल (सेवानिवृत्त) के स्थान पर श्री बलराम सिंह ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

शिव अनंत तायल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्रमांक 1196/नगानि/वि.यो.-वाड्रफनगर/2021.—वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लमोरी के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र के भाग-1 में क्र. 14 रायपुर शुक्रवार दिनांक 02 अप्रैल 2021 अनुसार प्रकाशित किया गया था. उक्त राजपत्र में प्रकाशित हिन्दी एवं अंग्रेजी सूचना को निरस्त करते हुए निम्न सूचना प्रकाशित किया जाता है।

प्रारूप-पांच

वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लमोरी के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 30-10-2020 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्राप्त नहीं हुआ है।

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा की उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 15 दिवस तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :-

1. संभागीय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, वाड्रफनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

FORM-V

No. 1196/नगानि/वि.यो.-वाड्रफनगर/2021.—The existing land use map for Lamori in Wadrafnagar Planning area was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 30-10-2020 and objections and suggestion were invited from the public under the provisions of sub-section (2) of the said section. Any objection or suggestion, modification have not filed in the said planning area.

Now, the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of Section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam. Which shall be conclusive evidence of the fact that the above map has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following offices of—

- (i) Divisional Commissioner, Surguja (C.G.)
- (ii) District Collector, Balrampur-Ramanujganj (C.G.)
- (iii) Town and Country Planning Regional office Ambikapur (C.G.)
- (iv) Nagar Panchayat, Wadrafanagar, Distt.-Balrampur-Ramanujganj (C.G.)

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 6 जुलाई 2021

प्ररूप-पांच
(नियम 11 देखिए)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन का प्ररूप

क्रमांक 505/वर्त. भू.उप.-पोड़ी-उप./नग्रा.नि./2021.—पोड़ी-उपरोड़ा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 12-02-2021 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

- 1. संभागीय आयुक्त बिलासपुर (छ.ग.)
- 2. जिला कलेक्टर कोरबा (छ.ग.)
- 3. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.)
- 4. कार्यालय जनपद, पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

के. एस. कंवर,
उप-संचालक.

**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)**

भानुप्रतापपुर, दिनांक 11 जून 2021

उद्घोषणा-पत्र

**भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्रकरण क्र./10/अ-82/2017-18,
ग्राम भेजा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़**

क्रमांक/599/अविअ/रीडर-2/2021.—चूंकि निम्नांकित ग्राम भेजा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. में स्थिति भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं का अपने अधिकारों के साथ एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में दिनांक 26-06-2021 दिन शनिवार को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				खसरा नं.	रकबा हे.	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	भेजा	भानुप्रतापपुर	कुमार साय पिता धीरसाय गोंड	311	0.11	0.275	धनहा	-	सागोन 5 नग महुआ 2 नग सेन्हा 1 नग	
2.	भेजा	भानुप्रतापपुर	बुल्लूराम पिता चमरा गोंड	290	0.05	0.125	धनहा	-	महुआ 1 नग	
3.	भेजा	भानुप्रतापपुर	सनकाय बेवा सिंगराम गोंड	305	0.06	0.15	धनहा	-	हर्रा 2 नग	
4.	भेजा	भानुप्रतापपुर	अंकालू पिता मेहतर गोंड	289/9	0.08	0.2	धनहा	-	परसा 3 नग सेन्हा 5 नग सागोर 6 नग	
5.	भेजा	भानुप्रतापपुर	जयमोतिन पति दयाराम	281	0.28	0.7	धनहा	-	हर्रा 5 नग सागोन 27 नग परसा 2 नग सेन्हा 4 नग आम 1 नग बांसभीरा 1 नग तिनसा 1 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									धावड़ा 1 नग महुआ 1 नग मुंडी 1 नग अन्य 1 नग	
6.	भेजा	भानुप्रतापपुर	जयराम पिता घासीराम गोंड़	278	0.24	0.6	धनहा	-	तेंदू 1 नग साजा 4 नग महुआ 1 नग सेन्हा 4 नग गिरची 1 नग हर्रा 1 नग चार 1 नग कुसुम 1 नग	
7.	भेजा	भानुप्रतापपुर	हलालखोरी पिता उजियार गोंड़	18	0.2	0.5	धनहा	-	साजा 1 नग सेन्हा 5 नग	
8.	भेजा	भानुप्रतापपुर	सुखराम पिता रामजीराम गोंड़	19	0.08	0.2	धनहा	-	सेन्हा 6 नग हर्रा 1 नग	
9.	भेजा	भानुप्रतापपुर	फततेसिंह पिता फगनूराम गोंड़	11/4	0.13	0.325	धनहा	-	हर्रा 3 नग बांसभीरा 1 नग साजा 1 नग	
10.	भेजा	भानुप्रतापपुर	प्रभुराम पिता जेठुराम गोंड़	9	0.05	0.125	धनहा	-	सेन्हा 1 नग हर्रा 2 नग महुआ 1 नग कुसुम 1 नग	
11.	भेजा	भानुप्रतापपुर	कवलसिंह पिता सनकूर गोंड़	276/1 276/2	0.22 0.13	0.55 0.325	धनहा धनहा	-	महुआ 2 नग ईमली 1 नग बांसभीरा 3 नग सेन्हा 19 नग सागोन 2 नग परसा 2 नग रेला 1 नग साजा 1 नग कुसुम 1 नग हर्रा 2 नग	
12.	भेजा	भानुप्रतापपुर	धरमीन बेवा बिशल गोंड़	275	0.08	0.2	धनहा	-	सेन्हा 5 नग	
13.	भेजा	भानुप्रतापपुर	दुकालूराम पिता मेहतर गोंड़	283/11	0.04	0.1	धनहा	-	सेन्हा 4 नग परसा 1 नग साजा 1 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14.	भेजा	भानुप्रतापपुर	फूलसिंह पिता बीसनाथ गोंड	265	0.05	0.125	धनहा	-	कुसुम 1 नग	
15.	भेजा	भानुप्रतापपुर	रिंगूराम पिता बीसूराम गोंड	262	0.04	0.1	धनहा	-	अमरूद 1 नग सल्फी 1 नग	

आज दिनांक 09-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

भानुप्रतापपुर, दिनांक 11 जून 2021

उद्घोषणा-पत्र

**भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्रकरण क्र./11/अ-82/2017-18,
ग्राम तेलम्मा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़**

क्रमांक/600/अविअ/रीडर-2/2021.—चूँकि निम्नांकित ग्राम तेलम्मा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. में स्थिति भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं का अपने अभिकर्ता के साथ एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में दिनांक 26-06-2021 दिन शनिवार को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				खसरा नं.	रकबा हे.	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	तेलम्मा	भानुप्रतापपुर	अनुजराम पिता परदेशी जाति मरार	4/1	0.25	0.626	मटासी	-	कुसुम 1 नग कुमही 1 नग बांस भीरा 1 नग	
2.	तेलम्मा	भानुप्रतापपुर	सगनू पिता परदेशी जाति मरार	4/2	0.20	0.5	मटासी	-	परसा 1 नग छिंद 2 नग	
3.	तेलम्मा	भानुप्रतापपुर	ईतवारू राम पिता रमऊ जाति गोड़	8/1	0.13	0.325	मटासी	-	परसा 2 नग बांस भीरा 1 नग छिंद 1 नग	
4.	तेलम्मा	भानुप्रतापपुर	अमिता बाई पति महारू जाति गोंड	8/2	0.08	0.2	मटासी	-	परसा 2 नग छिंद 6 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	तेलम्मा भानुप्रतापपुर	फूलबाई बेवा सोनऊराम जाति गोंड	18/2	0.07	0.175	मटासी	-	-		

आज दिनांक 09-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

भानुप्रतापपुर, दिनांक 26 जून 2021

उद्घोषणा-पत्र

**भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्रकरण क्र./10/अ-82/2017-18,
ग्राम भेजा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़**

क्रमांक/650/अविअ/रीडर-2/2021.—चूँकि निम्नांकित ग्राम भेजा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. में स्थिति भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं का अपने अभिकर्ता के साथ एवं न्यायालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के अंदर उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
		खसरा नं.	रकबा हे.	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	कुमार साय पिता धीरसाय, गोंड	311	0.11	0.275	धनहा	-	सागोन 5 नग महुआ 2 नग सेन्हा 1 नग	
2.	बुल्लूराम पिता चमरा गोंड	290	0.05	0.125	धनहा	-	महुआ 1 नग	
3.	सनकाय बेवा सिंगराम गोंड	305	0.06	0.15	धनहा	-	हर्रा 2 नग	
4.	अंकालू पिता मेहतर गोंड	289/9	0.08	0.2	धनहा	-	परसा 3 नग सेन्हा 5 नग सागोर 6 नग	
5.	जयमोतिन पति दयाराम	281	0.28	0.7	धनहा	-	हर्रा 5 नग सागोन 27 नग परसा 2 नग सेन्हा 4 नग आम 1 नग बांसभीरा 1 नग तिनसा 1 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							धावड़ा 1 नग महुआ 1 नग मुंडी 1 नग अन्य 1 नग	
6.	जयराम पिता घासीराम गोंड़	278	0.24	0.6	धनहा	-	तेंदु 1 नग साजा 4 नग महुआ 1 नग सेन्हा 4 नग गिरची 1 नग हरा 1 नग चार 1 नग कुसुम 1 नग	
7.	हलालखोरी पिता उजियार गोंड़	18	0.2	0.5	धनहा	-	साजा 1 नग सेन्हा 5 नग	
8.	सुखराम पिता रामजीराम गोंड़	19	0.08	0.2	धनहा	-	सेन्हा 6 नग हरा 1 नग	
9.	फततेसिंह पिता फगनूराम गोंड़	11/4	0.13	0.325	धनहा	-	हरा 3 नग बांसभीरा 1 नग साजा 1 नग	
10.	प्रभुराम पिता जेठुराम गोंड़	9	0.05	0.125	धनहा	-	सेन्हा 1 नग हरा 2 नग महुआ 1 नग कुसुम 1 नग	
11.	कवलसिंह पिता सनकूर गोंड़	276/1 276/2	0.22 0.13	0.55 0.325	धनहा धनहा	-	महुआ 2 नग ईमली 1 नग बांसभीरा 3 नग सेन्हा 19 नग सागोन 2 नग परसा 2 नग रेला 1 नग साजा 1 नग कुसुम 1 नग हरा 2 नग	
12.	धरमीन बेवा बिशल गोंड़	275	0.08	0.2	धनहा	-	सेन्हा 5 नग	
13.	दुकालूराम पिता मेहतर गोंड़	283/11	0.04	0.1	धनहा	-	सेन्हा 4 नग परसा 1 नग साजा 1 नग	
14.	फूलसिंह पिता बीसनाथ गोंड़	265	0.05	0.125	धनहा	-	कुसुम 1 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.	रिंगूराम पिता बीसूराम गोंड़	262	0.04	0.1	धनहा	-	अमरूद 1 नग सल्फी 1 नग	

आज दिनांक 26-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

भानुप्रतापपुर, दिनांक 26 जून 2021

उद्घोषणा-पत्र

**भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्रकरण क्र./11/अ-82/2017-18,
ग्राम तेलम्मा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़**

क्रमांक/651/अविअ/रीडर-2/2021.—चूंकि निम्नांकित ग्राम तेलम्मा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. में स्थिति भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं का अपने अभिकर्ता के साथ इस न्यायालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के अंदर उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
		खसरा नं.	रकबा हे.	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	अनुजराम पिता परदेशी जाति मरार	4/1	0.25	0.626	मटासी	-	कुसुम 1 नग कुगही 1 नग बांस भीरा 1 नग	
2.	सगनू पिता परदेशी जाति मरार	4/2	0.20	0.5	मटासी	-	परसा 1 नग छिंद 2 नग	
3.	ईतवारू राम पिता रमऊ जाति गोड़	8/1	0.13	0.325	मटासी	-	परसा 2 नग बांस भीरा 1 नग छिंद 1 नग	
4.	अमिता बाई पति महारू जाति गोंड़	8/2	0.08	0.2	मटासी	-	परसा 2 नग छिंद 6 नग	
5.	फूलबाई बेवा सोनऊराम, जाति गोंड़	18/2	0.07	0.175	मटासी	-	-	

आज दिनांक 26-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

हस्ता./-

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं (भू-अर्जन) अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st July 2021

No. 485/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office (S) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Dongargarh	Pendra-Road	Gaurela-Pendra-Marwahi	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Mohan Singh Korram, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Durg	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Santosh Thakur, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Balod	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Smt. Shyamwati Maravi, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Dantewara	Balod	Balod	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Smt. Rashmi Netam, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Baikunthpur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Smt. Yashoda Nag, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Durg	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Note : The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3(2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of service) Rules, 2006, however, on completion of five years of continuous service as Civil Judge Class-I/senior Civil Judge, the conferment of such benefit shall be made on the appraisal of the work and performance by the High Court.

Bilaspur, the 1st July 2021

No. 486/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I for the Revenue District mentioned in Column

No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Ganga Patel, III Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Durg	Durg	II Civil Judge Class-I
2.	Shri Harendra Singh Nag, II Civil Judge Class-I.	Durg	Dongargarh	Rajnandgaon	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-I.
3.	Shri Harish Chandra Mishra, Deputy Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Law Department.	New Delhi	Korba	Korba	II Civil Judge Class-I
4.	Smt. Shweta Shrivastava, Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Service Authority.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I
5.	Smt. Sweta Upadhyaya Gaur, II Civil Judge Class-I.	Jagdalpur	Raipur	Raipur	VII Civil Judge Class-I.
6.	Shri Umesh Kumar Upadhyay, Secretary, District Legal Services Authority.	Raipur	Durg	Durg	IV Civil Judge Class-I
7.	Ms. Seema Pratap Chandra, III Civil Judge Class-I.	Korba	Dhamtari	Dhamtari	II Civil Judge Class-I
8.	Shri Gerjesh Pratap Singh, II Civil Judge Class-I.	Dhamtari	Raipur	Raipur	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
9.	Shri Hemant Kumar Ratre, III Civil Judge Class-I.	Mahasamund	Kasdol	Baloda-bazar	Civil Judge Class-I
10.	Smt. Archana Bhaskar, V Civil Judge Class-I	Durg	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	II Civil Judge Class-I
11.	Shri Brijesh Rai, Secretary District Legal Service Authority.	Bilaspur	Korba	Korba	III Civil Judge Class-I
12.	Smt. Ravinder Kaur, Officiating Chief Judicial Magistrate.	Gaurela-Pendra-Marwahi	Mahasamund	Mahasamund	III Civil Judge Class-I
13.	Smt. Anita Dhruw, Civil Judge Class-I.	Kasdol	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	II Civil Judge Class-I

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्रमांक 6295/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा अपने घोषित कार्य स्थल दंतेवाड़ा के अतिरिक्त बचेली में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 6295/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that Ist Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Dantewara in addition to his place of sitting at Dantewara Declared shall also sit at Bacheli for a week in every month.

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.
